विवरण

राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के लिए साक्षरता दरें, 1991

भारत/राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश		साक्षरता दर 1991
भारत*		52.28
राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	44.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.59
3.	बिहार	38.48
4.	गोवा	75.51
5.	गुजरात	61.29
6.	हरियाणा	55.85
7.	हिमाचल प्रदेश	63.86
8.	कर्नाटक	56.04
9.	केरल	89.79
10.	मध्य प्रदेश	44.20
11.	महाराष्ट्र	64.87
12.	मणिपुर	59.89
13.	मेघालय	49.10
14.	मिजोरम	82.27
15.	नागालैंड	61.65
16.	उड़ीसा	49.09
17.	पंजाब	58.51
18.	राजस्थान	38.55
19.	सिक्किम	56.94
20.	तमिलनाडु	62.66
21.	त्रिपुरा	60.44
22.	उत्तर प्रदेश	41.60
23.	पश्चिम बंगाल	57.70
24.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	75.29
संघ शासित प्रदेश		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	73.02
2.	चंडीगढ़	77.81
3.	दादर व नगर हवेली	40.71
4.	दमन व दियू	71.20
5.	लक्षद्वीप	81.78
6.	पांडिचेरी	74.74

*असम व जम्मू कश्मीर शामिल नहीं।

गोबर तथा भूसे-पत्तों का उपयोग न किया जाना

2017. **श्री सोमपाल:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में पशुओं के गोबर, फसलों के बचे हुए भूसे-पत्ते आदि और शहरी क्षेत्रों में कूड़ा-करकट भारी मात्रा में बेकार ही चले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनके मद-वार आंकड़े क्या-क्या हैं और भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए इनका किस ढंग से उपयोग किया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) और (ख) देश में गोबर, फसलों के बचे हुए भूसे-पत्ते तथा कूड़ा-करकट की सही मात्रा का निर्धारण करना कठिन है। तथापि, यह अनुमान है कि फसलों के कूड़ा करकट, पशुओं के गोबर तथा शहर की रद्दी की वार्षिक उपलब्धता क्रमशः 275 मि०मी० टन, 1029 मि०मी० टन तथा 25 मिलियन मी० टन है। गोबर का लगभग 60-70 प्रतिशत और फसलों के कूड़ा-करकट तथा ग्रामीण रद्दी का 25 प्रतिशत प्रयोग मृदा के उपजाऊपन में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों से पता लगता है कि किसानों द्वारा लगभग 278 मिलियन मी० टन ग्रामीण तथा 6.4 मिलियन मी० टन शहरी कंपोस्ट खाद तैयार तथा प्रयोग की जाती है।

(ग) और (घ) आर्गेनिक खाद के मेल से उर्वरक

के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय "उर्वरक के संतुलित व समेकित प्रयोग" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा कम खपत वाले तथा वर्षासिंचित क्षेत्रों में उर्वरक प्रयोग के विकास की राष्ट्रीय परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत, आर्गेनिकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जैविक खाद पर प्रशिक्षण देने, कम्पोस्ट यूनिटें स्थापित करने तथा कम्पोस्ट खाद बनाने के उन्नत तरीकों के प्रदर्शन संबंधी कार्य शुरू किए गये हैं। गाय के गोबर, फसल के बचे अवशेष, आदि के उपयोग की उचित प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत सात स्थानों में आर्गेनिक अवशेष के माइक्रोबायल सड़ाव तथा शहर के कूड़ा-करकट के पुनरावर्तन की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना स्थापित की है।

Procurement of Foodgrains for Mid-Day Meals through PDS

2018. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the newly introduced mid-day meal scheme for primary school children is operational and how many schools are to be covered in the initial phase;

(b) whether the requirements of foodgrains for this scheme are proposed to be drawn through the Public Distribution System;

(c) whether Government are aware that the Public Distribution System is already stretched and will not be able to handle this additional burden; and

(d) if so, whether government would consider appointing any other Central Agency to handle foodgrains distribution meant for mid-day meal scheme and other public nutrition scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION) (DR. KRUPASINDHU BHOI): (a) All States and Union Territories have informed that National Programme of Nutritional Support to Primary Education is operational in their States/UTs. About 2.25 lakh Schools are being covered under the Programme in the initial phase during 1995-96.

(b) to (d) The foodgrains are being made available to the local bodies from the nearest FCI godowns. The States have the flexibility to decide the modalities of transportation and delivery to the Panchayats and Nagarpalikas.

Lower Growth Rate of Foodgrains Production

2019. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether rabi and kharif foodgrains production for 1995-96 estimated at 191 million tonnes is showing a lower growth rate of 1.6 per cent as compared to 2.7 per cent in 1994-95;

(b) whether the overall agricultural growth rate is also lower than last year's;

(c) if so, the details and the reasons therefor;

(d) the steps taken by Government to remove the effect of negative subsidies and other distortions adversely affecting the agricultural sector; and

(e) whether Government propose to free domestic trade in farm output, remove export restrictions and bring domestic procurement prices at par with international prices; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (c) Firm estimates of foodgrain production for 1995-96 are not yet available since the sowing of Rabi crops is still in progress. However, as per preliminary estimates the foodgrains production in 1995-96 may not show any significant growth over that in 1994-95 due to shortfall in kharif production owing to erratic monsoon. This